

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिनांक 6.11.2026 से 12.11.2026

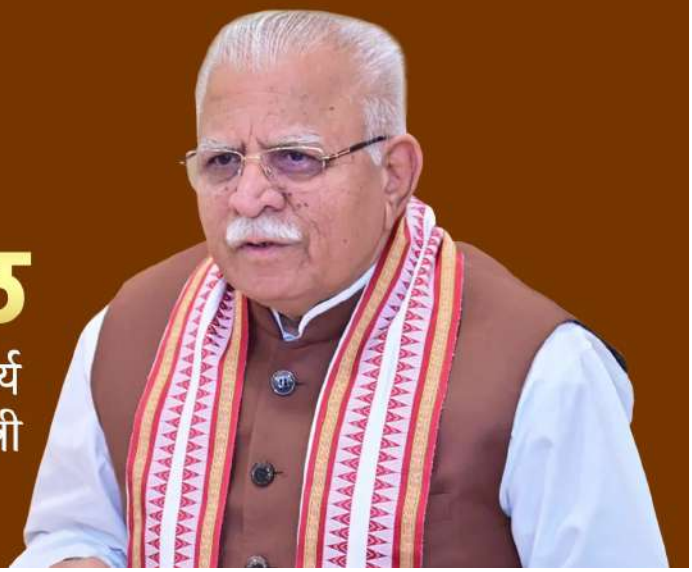
10वाँ संस्करण

सभी संस्करण यहाँ पढ़ें:



श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने **स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26** के विजेता शहरों को किया सम्मानित

2. शहरी आवास को नई गति: **अहमदाबाद में PMAY-U** के तहत आवासों का लोकार्पण एवं नई परियोजना का शिलान्यास

3. **नमो भारत** की बढ़ती लोकप्रियता: **5 करोड़ यात्राएँ पूरी**, त्योहारों पर अतिरिक्त ट्रेन सेवाएँ

4. देश के 76 शहरों में **SVANidhi Mahotsavs**, स्ट्रीट वेंडर्स की उपलब्धियों और उद्यमशीलता का उत्सव

5. एनबीसीसी के वित्तीय प्रदर्शन में शानदार उछाल, दूसरी तिमाही में एकल पीएटी 30.54% बढ़ा

6. DMRC ने राष्ट्रीय **साइबर सुरक्षा जागरूकता** माह मनाया, साइबर सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ

7. **NBCC के WHO-SEARO भवन** को GRIHA की अनंतिम 5-स्टार रेटिंग एवं प्रशंसा पुरस्कार

साप्ताहिक सूचना पत्र

6.11.2026 से 12.11.2026

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

11 नवंबर, 2026

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 के विजेता शहरों को किया सम्मानित

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के शहरी विकास विभाग (DoUD) द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26' पुरस्कार समारोह में देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की गरिमामयी उपस्थिति में विजेता शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस वर्ष सात श्रेणियों के अंतर्गत 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं:

* स्वच्छ शहर जोड़ी (SSJ)
* सुपर स्वच्छ लीग के स्वच्छ शहर
* पांच जनसंख्या श्रेणियों में स्वच्छ शहर
* स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन (नदी तट का स्वच्छ शहर)
* स्वच्छ तटीय शहर
* स्वच्छ हिमालयी शहर
* राज्य का पहला स्वच्छ शहर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल किसी एक संस्था के प्रयासों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों की सहभागिता, व्यवहार में बदलाव, प्रशासनिक जवाबदेही और निरंतर जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। कम उम्र से ही बच्चों में स्वच्छता के संस्कार विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल करने तथा बच्चों एवं युवाओं के साथ इन विषयों पर निरंतर संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में सार्थक प्रगति तभी संभव है, जब नागरिक, स्थानीय प्रशासन और स्वच्छताकर्मी मिलकर कार्य करें तथा स्वच्छताकर्मियों के जमीनी अनुभवों एवं सुझावों और नागरिकों की प्रतिक्रिया को उचित महत्व दिया जाए। उन्होंने स्वच्छ शहर जोड़ी (Swachh Shehar Jodi) पहल की भी सराहना करते हुए इसे आपसी सहयोग एवं सीखने का एक नया आयाम बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से शहर एक-दूसरे के नवाचारों को साझा कर सकते हैं, समाधानों को आजमा सकते हैं और शहरी स्वच्छता के उच्च मानक हासिल करने के लिए एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं।





सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने शहरी स्वच्छता के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है।

वर्ष 2014 से अब तक हासिल की गई प्रगति को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि शहरी कचरे का प्रसंस्करण 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है, जबकि घर-घर कचरा संग्रहण का दायरा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि पुराने कचरा स्थलों (Legacy Waste Dumpsites) के निस्तारण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लगभग 11,000 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर उसका उत्पादक उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने राज्यों को अपने-अपने स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसके तहत राज्यों के भीतर शहरों एवं कस्बों की स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग की जा सके। इससे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और छोटे शहरों को भी अपने स्वच्छता मानकों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

आवासन एवं शहरी कार्य विभाग (DoUD), MoHUA के सचिव श्री सतेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि पिछले एक दशक में स्वच्छ सर्वेक्षण ने मिशन के अंतर्गत शहरी स्वच्छता सेवाओं के आकलन और उनमें सुधार की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। साथ ही, इसने जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। MoHUA के सचिव ने आगे कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण केवल एक आकलन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वच्छ भारत के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध लाखों लोगों की सामूहिक आवाज है। उन्होंने कहा, "आज का दिन स्वच्छता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे शहरों और नागरिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के उत्सव का अवसर है।"

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 के परिणाम शहरी भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर हो रही प्रगति को दर्शाते हैं। इस दौरान 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया है। इस बदलाव में छोटे शहरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यह दर्शाता है कि निरंतर प्रयासों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सभी आकार के शहरों और कस्बों में स्वच्छता जन आंदोलन को गति मिल रही है।

शहरी कचरा प्रबंधन में उत्कृष्टता को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' श्रेणी में अहमदाबाद (मेंटर)–साणंद (मेंटी), इंदौर (मेंटर)–देपालपुर (मेंटी) तथा तिरुपति (मेंटर)–कुप्पम (मेंटी) ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान हासिल किए।

सुपर स्वच्छ लीग की स्वच्छ शहर श्रेणी में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। वहीं, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC), जबलपुर और लखनऊ ने देश के शीर्ष तीन स्वच्छ शहरों के रूप में स्थान प्राप्त किया।

इस वर्ष पहली बार 'स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन', 'स्वच्छ कोस्टल टाउन' और 'क्लीन हिमालयन सिटी' श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान किए गए। इन नई श्रेणियों के माध्यम से नदी तटों, तटीय क्षेत्रों और हिमालयी शहरों में स्वच्छता के प्रयासों को विशेष पहचान दी गई।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

9 नवंबर, 2026

शहरी आवास को नई गति: अहमदाबाद में PMAY-U के तहत आवासों का लोकार्पण एवं नई परियोजना का शिलान्यास

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के ISSR घटक के अंतर्गत अहमदाबाद के रामापीरनो टेकरो में दो आवासीय परियोजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए 1,176 आवासों एवं 16 दुकानों का लोकार्पण किया।



इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम, वाडज में 2,002 आवासीय इकाइयों वाली स्लम पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया।

इसके अतिरिक्त, माननीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के AHP घटक के अंतर्गत 7,825 आवासीय इकाइयों के आवंटन हेतु आयोजित ड्रॉ में भी शामिल हुए। यह पहल पात्र शहरी परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

11 नवंबर, 2026

नमो भारत की बढ़ती लोकप्रियता: 5 करोड़ यात्राएँ पूरी, त्योहारों पर अतिरिक्त ट्रेन सेवाएँ





नमो भारत कॉरिडोर ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 5 करोड़ कम्यूटर जर्नी का आंकड़ा पार कर लिया है। 21 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड के उद्घाटन के साथ परिचालन शुरू करने वाले इस कॉरिडोर को 22 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके बाद से यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। नमो भारत की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ पहले 1 करोड़ यात्राओं का आंकड़ा पार करने में 574 दिन लगे थे, वहीं अंतिम 1 करोड़ यात्राएँ महज 93 दिनों में पूरी हुईं।

माननीय प्रधानमंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर को सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए निर्धारित समय-सीमा में परियोजना के पूर्ण होने, 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति और 99 प्रतिशत से अधिक की शानदार समयबद्धता की विशेष रूप से सराहना की है।

यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के दौरान सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एनसीआरटीसी ने भाई दूज के अवसर पर 11 नवंबर को दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों की 32 अतिरिक्त ट्रिप्स संचालित कीं। त्योहार के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई इस पहल के तहत ट्रेनें 10 मिनट से कम की फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध रहीं।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

11 नवंबर, 2026

देश के 76 शहरों में SVANidhi Mahotsavs, स्ट्रीट वेंडर्स की उपलब्धियों और उद्यमशीलता का उत्सव









PM SVANidhi Scheme की उपलब्धियों और स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करने के लिए देश के 76 शहरों में SVANidhi Mahotsavs आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का उत्सव मनाना, स्ट्रीट वेंडर्स एवं उनके परिवारों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, हितधारकों की सहभागिता सुदृढ़ करना तथा योजना के प्रति जागरूकता और पहुँच का विस्तार करना है, ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स इसके लाभ प्राप्त कर सकें।

अब तक अहमदाबाद, आइजोल, अमृतसर, कटक, देहरादून, धनबाद, डिब्रूगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर हैदराबाद, गुरुग्राम, हरिद्वार, मदुरै, प्रयागराज, पुडुचेरी, राजकोट, रुद्रपुर, श्रीनगर, श्री विजय पुरम, सूरत, वडोदरा और यमुनानगर सहित 22 शहरों में SVANidhi Mahotsavs आयोजित किए जा चुके हैं। इन आयोजनों में स्ट्रीट वेंडर्स, उनके परिवारों और विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संबंधित शहरों एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों, Municipal Commissioners, Mayors तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इन आयोजनों की गरिमा बढ़ाई।

SVANidhi Mahotsavs के दौरान ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण, PM SVANidhi Credit Cards एवं UPI IDs जारी करना, लाभार्थियों का सम्मान, सफलता की कहानियों का साझा करना, SVANidhi Bazaars का आयोजन, स्थानीय व्यंजनों एवं हस्तशिल्प का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान और सामुदायिक सहभागिता जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

ये आयोजन स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों की उपलब्धियों को पहचानने एवं सम्मानित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा, खेल, कला एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के बच्चों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही, ये पहल स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने तथा समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

5 नवंबर, 2026

एनबीसीसी के वित्तीय प्रदर्शन में शानदार उछाल, दूसरी तिमाही में एकल पीएटी 30.54% बढ़ा

NBCC(India) Ltd. के निदेशक मंडल ने 5 नवंबर 2026 को आयोजित बैठक में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के परिणामों में कंपनी ने प्रमुख वित्तीय मानकों पर शानदार वृद्धि दर्ज की।

दूसरी तिमाही (Q2) में एकल आधार पर प्रचालन आय 37.78% बढ़कर ₹2,889.62 करोड़ हो गई, जबकि ईबीआईटीडीए 153.98% की वृद्धि के साथ ₹219.03 करोड़ पर पहुंच गया। कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 38.09% बढ़कर ₹291.80 करोड़ और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 30.54% बढ़कर ₹225.24 करोड़ रहा। समेकित आधार पर प्रचालन आय 16.54% बढ़कर ₹3,395.78 करोड़, ईबीआईटीडीए 115.28% बढ़कर ₹225.16 करोड़ और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 33.93% की वृद्धि के साथ ₹209.85 करोड़ दर्ज किया गया।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (एचा) में एकल आधार पर प्रचालन आय 25.54% बढ़कर ₹4,712.66 करोड़ हो गई, जबकि कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 31.14% की वृद्धि के साथ ₹375.89 करोड़ पर पहुंच गया। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 25% (₹0.25 प्रति शेयर) के दूसरे अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की।



6 नवंबर, 2026

DMRC ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाया, साइबर सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में अक्टूबर माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाया गया। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर रक्षा साइबर एजेंसी के महानिदेशक रियर एडमिरल संजय सचदेवा ने मुख्य संबोधन दिया।

इस अवसर पर डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में DMRC साइबर सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

कार्यक्रम का समापन तीसरे CISO राउंडटेबल कॉन्क्लेव के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) ने व्यापक सहभागिता की। कॉन्क्लेव के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत CISO ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख चिंताओं, चुनौतियों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया।





Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

5 नवंबर, 2026

NBCC के WHO-SEARO भवन को GRIHA की अनंतिम 5-स्टार रेटिंग एवं प्रशंसा पुरस्कार

NBCC(India) Ltd. द्वारा निष्पादित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (WHO-SEARO) भवन, नई दिल्ली को प्रतिष्ठित GRIHA की अनंतिम 5-स्टार रेटिंग तथा GRIHA प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनबीसीसी की ओर से श्री आदित्य चंद्रा, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.) और श्री दिनेश्वर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.) ने यह सम्मान प्राप्त किया।

यह परियोजना जनवरी 2019 में एनबीसीसी और WHO-SEARO का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई थी। मूल भवन के उसी भूखंड पर पुनर्विकसित इस भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग चार गुना बढ़कर 10,500 वर्ग मीटर से 40,500 वर्ग मीटर हो गया है। इस भवन में WHO India Country Office भी स्थापित किया गया है।

भवन की ऐतिहासिक एवं विरासत संबंधी धरोहरों को नए परिसर में सावधानीपूर्वक पुनर्स्थापित और एकीकृत किया गया है। इनमें विख्यात कलाकार एम.एफ. हुसैन द्वारा वर्ष 1963 में निर्मित भित्ति चित्र तथा पुर्तगाली टाइलों से बने भित्ति चित्र शामिल हैं। इस नए भवन का उद्घाटन दिसंबर 2025 में किया गया था।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

नवभारत टाइम्स
(6 नवंबर, 2026)

लोगों को पसंद आ रहे DDA के फ्लैट्स, बिक्री में 80% उछाल

पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले LIG, MIG और HIG फ्लैटों की बिक्री का आंकड़ा भी पार

2 शहर

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

डीडीए के फ्लैटों की मांग तेजी से बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर) में डीडीए ने 9,332 फ्लैट बेचे हैं। पिछले वित्त वर्ष इस अवधि में 5,198 फ्लैट बिके थे। इस तरह बिक्री में करीब 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीडीए के मुताबिक, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी तीनों श्रेणियों में इस साल अक्टूबर तक हुई बिक्री पिछले पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े से ज्यादा रही है।

डीडीए ने अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 5,171 एलआईजी फ्लैट बेचे, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 3,547 फ्लैट बिके थे। इसी तरह एमआईजी श्रेणी में सात महीने में 1,704 फ्लैटों की बिक्री हुई, जबकि पिछले पूरे साल यह आंकड़ा 1,580 था। एचआईजी श्रेणी में भी 820 फ्लैट बिके, जबकि पिछले वित्त वर्ष में कुल 404 फ्लैटों की बिक्री हुई थी।

7 महीने में बिके 9,332 घर, नरेला में सबसे ज्यादा बायर्स

नरेला में 90% से ज्यादा बिक्री : डीडीए की कुल बिक्री में नरेला की हिस्सेदारी 90 फीसदी से ज्यादा रही है। डीडीए के अनुसार, अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2), प्रस्तावित रिंगरोड-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर और एकुकेशन हब जैसी परियोजनाओं से इलाके की आवासीय संभावनाएं बढ़ रही हैं। सेक्टर जी-2 से जी-6 में 138 हेक्टेयर में एजुकेशन हब प्रस्तावित है। यहां कई यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों को जमीन आवंटित की गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशल क्षेत्र और दूसरी नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

डीडीए ने अपनी तीन आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट बुक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। इनमें डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, कर्मयोगी आवास योजना 2026 और नागरिक आवास योजना 2026 शामिल हैं। इन योजनाओं में फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (एफसीएफएस) आधार पर उपलब्ध हैं। इच्छुक खरीदार डीडीए के आवास पोर्टल के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। डीडीए के मुताबिक, फ्लैट प्रॉस्पेक्ट और रहने के लिए तैयार हैं। खरीदारों के लिए सेफ्ट फ्लैट देखने की सुविधा भी है। डीडीए ने बिक्री में बढ़ोतरी का श्रेय आवास योजनाओं की लगातार निगरानी, ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया और खरीदारों तक जानकारी पहुंचने के प्रयासों को दिया है।

हिंदुस्तान
(6 नवंबर, 2026)

उपहार : दिल्ली में पांच लाख झुग्गीवालों को पक्का मकान मिलेगा

नई दिल्ली। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पांच लाख परिवारों को पक्के मकान का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए 'दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' अधिसूचित कर दी है। इससे करीब 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। नीति के तहत एक जनवरी 2025 तक स्थापित झुग्गी बस्तियों के पात्र परिवारों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा। यथास्थान पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा बस्ती या तीन किलोमीटर के दायरे में मकान देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि रोजगार और सामाजिक जीवन प्रभावित न हो। मकान आवंटन के बाद पांच वर्ष तक साझा सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का रखरखाव किया जाएगा। इसके बाद यह जिम्मेदारी लाभार्थी एसोसिएशन संभालेगी।

> सपना पूरा होगा P03

हिंदुस्तान
(8 नवंबर, 2026)

पीएम आवास योजना के लिए 1156 करोड़ जारी

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में 1,15,616 लाभार्थियों के दूसरी किस्त का ₹1,156.16 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

द पायनियर
(11 नवंबर, 2026)

गाजीपुर में दो हजार टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगेगा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गाजीपुर डंपसाइट पर प्रतिदिन 2000 टन ठोस कचरे के निस्तारण और उससे बिजली उत्पादन के लिए अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। प्लांट में उत्पादित बिजली की दर 7.39 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जिसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी है। सत्या शर्मा ने बताया कि परियोजना के लिए केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 122 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत चयनित कंपनी प्लांट का निर्माण, वित्तपोषण और संचालन करेगी। व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी 25 वर्षों तक इसका संचालन करेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए निगम की ओर से पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद कंपनी का चयन किया गया। बिजली की दर को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत डीईआरसी से नियामक मंजूरी मिली है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में बढ़ती कचरे की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। इस प्लांट के शुरू होने से प्रतिदिन 2000 टन कचरे का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकेगा।

जनसत्ता
(7 नवंबर, 2026)

दिवाली पर तीन मेट्रो लाइनों पर सुबह छह बजे से दौड़ेंगी ट्रेनें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) दिवाली के दिन तीन मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सुबह सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू करेगा और आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे चलेगी। डीएमआरसी ने एक बयान में बताया कि पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर रविवार को सामान्यतः सुबह सात बजे शुरू होने वाली मेट्रो सेवाएं सुबह छह बजे संबंधित टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी। ये शुरुआती सेवाएं पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार), मैजेंटा लाइन (बॉटनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक) तथा ग्रे लाइन (द्वारका-ककरोला-ढांसा बस स्टैंड) पर उपलब्ध होंगी।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक भास्कर
(6 नवंबर, 2026)

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट• पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 37.8 करोड़ से जी+8 संरचना में बनेंगे फ्लैट

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर मिलेगा, हातमा पहाड़ और खादगढ़ा में बनेंगे 180 आशियाने

भास्कर न्यूज | रांची

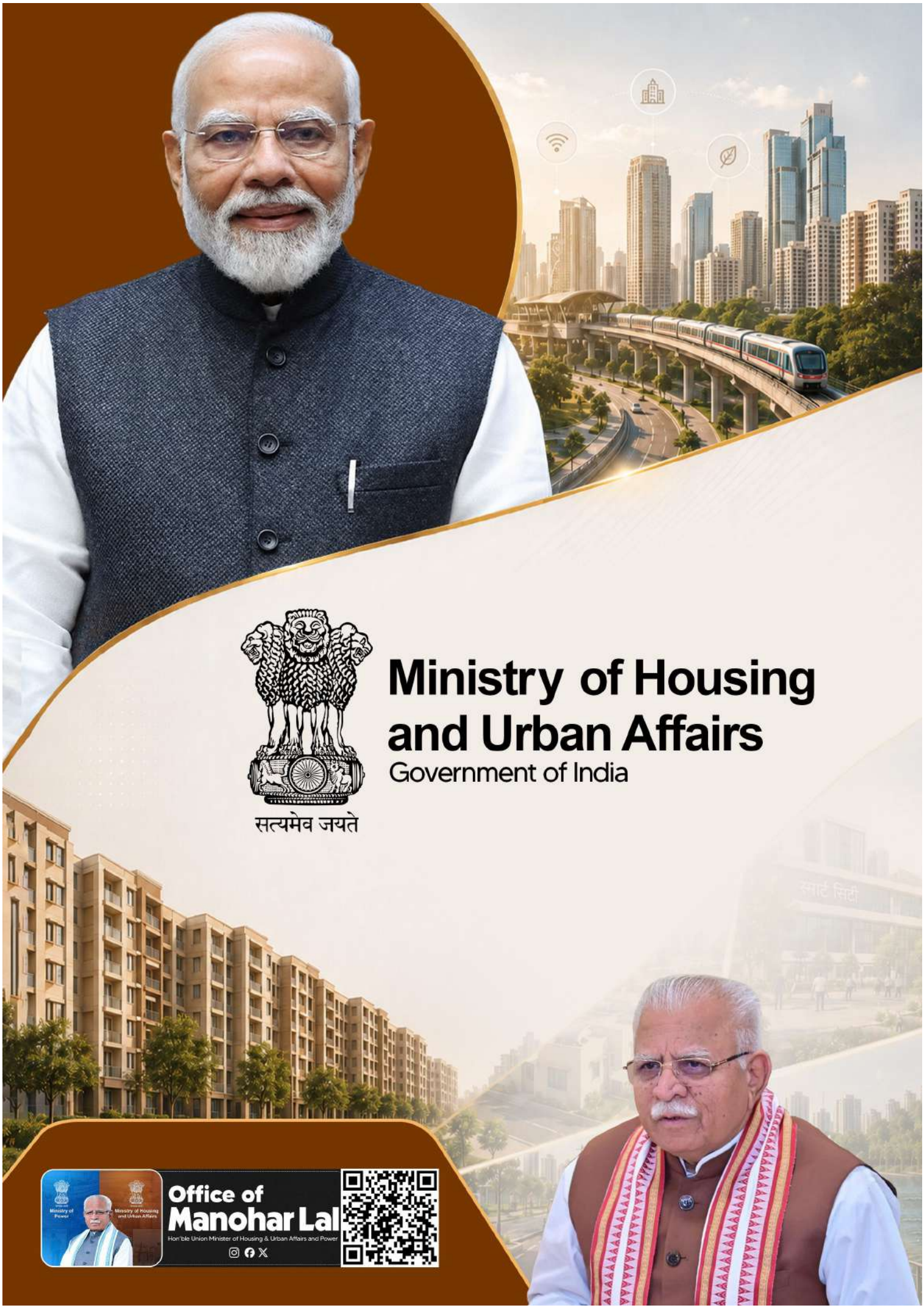
राजधानी में झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे मकानों में गुजर-बसर कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने पक्के घर का सपना अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के घटक-3 (अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट) के तहत रांची नगर निगम ने शहर के दो अलग-अलग इलाकों में कुल 180 बहुमंजिला आवासों के निर्माण का खाका तैयार किया है। इस क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने वार्ड संख्या-02 स्थित हातमा पहाड़ और वार्ड संख्या-29 स्थित मधुकम-खादगढ़ा में चिह्नित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर अभियंताओं को परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

नगर निगम की कार्ययोजना के अनुसार, दोनों ही स्थलों पर जी+8 (ग्राउंड प्लस 8 मंजिला) संरचना के ब्लॉक खड़े किए जाएंगे। प्रत्येक आवास आधुनिक 1-बीएचके प्रारूप (एक बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम) में डिजाइन किया जाएगा। परियोजना के पहले हिस्से के तहत वार्ड-02 के हातमा पहाड़ पर 15.40 करोड़ की लागत से दो ब्लॉक बनेंगे, जिनमें कुल 72 फ्लैट्स (प्रति ब्लॉक 36 आवास) तैयार होंगे। वहीं, वार्ड-29 के मधुकम-खादगढ़ा क्षेत्र में 194.90 डिसमिल भूमि पर 22.4 करोड़ की अनुमानित लागत से तीन ब्लॉक बनेंगे, जिनमें 108 आवास विकसित किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना सिर्फ चारदीवारी तक सीमित न रहे; परिसर में समुचित ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी/पब्लिक टॉयलेट और पर्याप्त नागरिक सुविधाएं अनिवार्य रूप से विकसित की जाएं।

1 बेडरूम, हॉल, किचन और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे फ्लैट्स

विवरण	हातमा पहाड़ परियोजना	मधुकम-खादगढ़ा परियोजना
वार्ड संख्या	वार्ड-02	वार्ड-29
जमीन का रकबा	चिह्नित पहाड़ी क्षेत्र	194.90 डिसमिल
प्रस्तावित ब्लॉक	02 ब्लॉक (जी+8)	03 ब्लॉक (जी+8)
कुल आवास	72 फ्लैट्स	108 फ्लैट्स
अनुमानित लागत	15.40 करोड़	22.40 करोड़

प्राथमिकता: ईडब्ल्यूएस वर्ग, आजसहीन परिवार और अतिक्रमण हटाओ अभियान में विस्थापित हुए लोग


Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power